चिप डिज़ाइन में भारत की बड़ी छलांग

डीएलआई योजना के तहत 23 नई चिप परियोजनाएं स्वीकृत

निगरानी, ऊर्जा मीटर, नेटवर्किंग में चिप समाधान का विकास

नई दिल्ली, 31 जुलाई. केंद्र सरकार ने देश में अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) डिज़ाइन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 'डिज़ाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना' के अंतर्गत 23 नई चिप-डिज़ाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है.

ये परियोजनाएं देश की घरेलू कंपनियों, नवाचार आधारित संस्थानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा संचालित की जा रही हैं. इन्हें निगरानी कैमरों, ऊर्जा मीटरों, लघुप्रक्रमक (माइक्रोप्रोसेसर) बौद्धिक संपदा और संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों के लिए चिप समाधान विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में दी. उन्होंने बताया कि डीएलआई योजना, भारत सरकार के 76,000 करोड़ रुपये के 'सेमीकॉन भारत कार्यक्रम' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में अर्धचालक और प्रदर्शक (डिस्प्ले) निर्माण का एक संपूर्ण पारितंत्र विकसित करना है. इस योजना के अंतर्गत चिप डिज़ाइन को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

चूंकि अर्धचालक डिज़ाइन और इसे व्यवसायिक रूप देने में अधिक लागत और लंबी विकास प्रक्रिया शामिल होती है, डीएलआई योजना डिज़ाइन अधोसंरचना और वित्तीय सहायता का एक संयोजन प्रदान करती है. इसमें प्रारंभिक नमूना निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन स्वचालन उपकरण और बौद्धिक संपदा संसाधनों तक पहुंच, साथ ही डिज़ाइन, विस्तार और उत्पादन के लिए धन सहायता शामिल है.

इस योजना के तहत कंपनियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 15 करोड़ रुपये प्रति आवेदन तक की प्रतिपूर्ति दी जा सकती है.

> यह उल्लेखनीय है कि डीएलआई योजना को दिसंबर 2021 में आरंभ किया गया था. तब से अब तक 278 शैक्षणिक संस्थानों और 72 नवाचार इकाइयों ने इसमें भाग लिया है, जिन्हें अत्याधुनिक डिज़ाइन उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है. अब तक 17 संस्थानों से 20 चिप डिज़ाइन को सफलतापूर्वक मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में निर्मित किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, 6 कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय अर्धचालक निर्माण केंद्रों में अपने प्रारूप का अंतिम नमूना तैयार कर लिया है और 10 नवाचार इकाइयों ने व्यवसायिक विस्तार के लिए निवेश भी प्राप्त किया है.

पीएम किसान संपदा योजना को मिला बूस्ट

केंद्र सरकार ने योजना के लिए 6,520 करोड़ की स्वीकृति दी

50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए 1,000 करोड़

MOFPI
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
सत्यमेव जयते Ministry of Food Processing Industri
Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

नई दिल्ली, 31 जुलाई . केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए ?6,520 करोड़ के कुल व्यय को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसमें 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए 1,920 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी शामिल है.

इस स्वीकृति में योजना के घटक %एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अधोसंरचना% के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अधोसंरचना के तहत 100 राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु धनराशि शामिल है, जो केंद्रीय बजट घोषणा के अनुरूप है.

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए लगभग 920 करोड़ का प्रावधान किया गया है. एकीकृत शीत श्रृंखला और गुणवत्ता अधोसंरचना दोनों ही इस योजना की मांग-आधारित घटक योजनाएं हैं. पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए रुचि पत्र आमंत्रण जारी किए जाएंगे. प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों की समुचित जांच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी. प्रस्तावित 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के क्रियान्वयन से प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक की कुल संरक्षण क्षमता बनने की संभावना है.

भारत में स्टारलिंक को मिली मंजूरी

जल्द शुरू होगी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

नयी दिल्ली, 31 जुलाई. अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस मिल गया है और इसके साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एक नीतिगत ढांचे को भी अंतिम रूप दे दिया गया है.

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. देश में पहली मोबाइल कॉल के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह घोषणा की गई.सिंधिया ने कहा, ''स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस दिया गया है. स्पेक्ट्रम आवंटन और गेटवे निर्माण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार कर लिया गया है ताकि सेवा शुरू करने में कोई बाधा न हो.गेटवे संरचना उपग्रह से डेटा को भारत में लाने और भारत के इंटरनेट ढांचे से जोड़ने के लिए जरूरी होगी.

भारती समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब और जियो एसईएस को भी उपग्रह आधारित संचार सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार है.सिंधिया ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की डिजिटल यात्रा एक हद तक असाधारण रही है.उन्होंने कहा,दूरदराज के गांवों से लेकर महानगरों तक डिजिटल पहुंच ने नागरिकों को सशक्त बनाया है और भारत को सस्ती एवं समावेशी प्रौद्योगिकी का वैश्विक अगुवा बना दिया है.

सरकार ने डिजिटल साक्षरता लक्ष्य पार किया

6.39 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को मिला आईटी प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान ने रचा कीर्तिमान

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOG
सत्यमेव जयते

नई दिल्ली, 31 जुलाई. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश के 250 अरब डॉलर से अधिक के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल कौशल की कमी को दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है.

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 6.39 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को प्रशिक्षण देकर अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया है. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में प्रमुख कौशल प्रशिक्षण की पहलें निम्नलिखित हैं-

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन (मार्च 2024 में शुरू)- वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नेतृत्व का लक्ष्य.

फ्यूचर स्किल्स प्राइम (राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के संघ के साथ साझेदारी)- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक तकनीक और त्रि-आयामी मुद्रण जैसे क्षेत्रों में 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन.

युवा एआई-कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-पाँच वर्षों में 43.6 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण/प्रमाणन प्रदान किया गया, जिसमें छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया.

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिज़ाइन एवं विनिर्माण योजनाएं- इस क्षेत्र में 4.93 लाख को प्रशिक्षण, 3.75 लाख को प्रमाणन और 1.38 लाख को रोजगार प्राप्त हुआ.

> इसके अतिरिक्त, कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवा वर्ग को प्रशिक्षण देने में सहयोग कर रहे हैं. अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 25.77 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 15.39 लाख को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है.

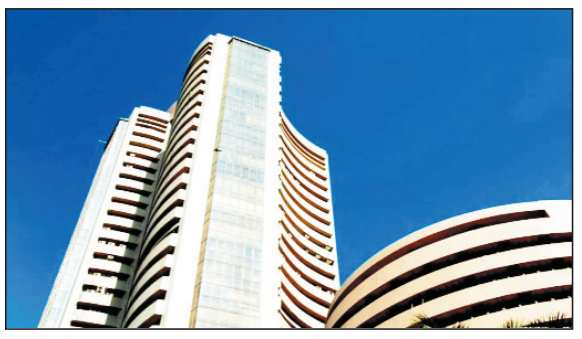

आयात शुल्क बढ़ने लुढ़का बाजार

सेंसेक्स 296 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

अमेरिकी आयात शुल्क और जुर्माने से निवेशकों में घबराहट

मुंबई, 31 जुलाई (वार्ता) अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 296.28 अंक यानी 0.36 प्रतिशत टूटकर 81,185.58 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86.70 अंक (0.35 प्रतिशत) नीचे 24,768.35 अंक पर बंद हुआ. लगातार दो दिन की तेजी के बाद बाजार में गिरावट आयी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदने के कारण जुर्माना लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद सुबह शेयर बाजारों में बिकवाली शुरू हो गयी. सेंसेक्स 786.36 अंक लुढ़ककर 80,695.50 अंक पर खुला और नीचे 80,695.15 अंक तक उतर गया.

एफएमसीजी कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलिवर और आईटीसी के साथ इटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों के शेयरों में लिवाली से सेंसेक्स ज्यादा नहीं टूटा. दोपहर बाद यह हरे निशान में भी गया, लेकिन आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली से फिर तेजी से गिरा. बुधवार की तुलना में 300 अंक से अधक चढ़कर एक समय यह 81,803.27 अंक पर भी पहुँच गया था. छोटी और मझौली कंपनियों में बिकवाली ज्यादा रही.

टाटा स्टील में दो फीसदी से अधिक की गिरावट

सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलिवर का शेयर करीब साढ़े तीन प्रतिशत की बढ़त में बंद हुआ. टाटा स्टील में दो फीसदी से अधिक की गिरावट रही. सनफार्मा, अडानी पोर्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी टूट गये. निफ्टी-50 भी पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 212.80 अंक नीचे 24,642.25 अंक पर खुला. इसका दिन का निचला स्तर 24,642.25 अंक रहा जबकि ऊपर यह 24,956.50 अंक तक मजबूत हुआ.

सरकार व्यापार हितों की करेगी रक्षा

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाया 25त्न शुल्क

भारत ने कहा-ट्रंप के बयान का अध्ययन जारी

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) सरकार ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने पर बुधवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है.

Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
Government of India

आयात शुल्क पर ट्रंप सरकार के फैसले के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति के एक बयान को देखा है. सरकार उसके निहितार्थों का अध्ययन कर रही है. बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीने से एक न्यायोचित, संतुलित और परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में लगे हुये हैं.

> सरकार की ओर से कहा गया है कि वह देश के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योमों के कल्याण के संवर्धन और उनके हितों की रक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है, सरकार अन्य सभी व्यापार समझौतों में अपने राष्ट्रीय हितों की हिफाजत के लिए हर आवश्यक कदम उठायेगी जिनमें हाल में ब्रिटेन के साथ हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता भी शामिल है

आईसीएआई ने एडीआर केंद्र की शुरुआत की

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने विवादों के त्वरित समाधान के लिए आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र (आईआईएसी) की स्थापना की घोषणा की है.

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार शाम यहाँ उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) भारत में कोई बाहर से आयी हुई सोच नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है.

जेन स्ट्रीट पर आयकर विभाग की नजर

मुंबई, 31 जुलाई.आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को बाजार में हेरफेर की आरोपी अमेरिकी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत कुछ ब्रोकिंग कंपनियों के परिसरों में सर्वेक्षण अभियान चलाया.

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.सूत्रों ने बताया कि विभाग जेन स्ट्रीट के खिलाफ हाल ही में पूंजी बाजार नियामक सेबी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में 'सत्यापन' अभियान चला रहा है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तीन जुलाई को दिए अपने अंतरिम आदेश में जेन स्ट्रीट को भारी मुनाफा कमाने के लिए वायदा एवं विकल्प बाजारों के साथ-साथ नकदी में भी दांव लगाकर सूचकांकों में हेरफेर करने का दोषी पाया. इससे, सेबी ने 'हेज फंड' को बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया और 4,843 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ जब्त कर लिया.

समाचार विशेष

लालू को फिर मिला सुपर सीएम का साथ!

विधानसभा चुनाव से पहले दी बड़ी जिम्मेदारी

पटना. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में लंबे समय तक सुपर सीएम की भूमिका में रहे पूर्व सांसद डॉ. रंजन प्रसाद यादव एकबार फिर राजद की मुख्यधारा की राजनीति में लौट आए हैं. राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है. यह पार्टी की सबसे बड़ी निर्णायक इकाई है.

ऐसे तो लालू-राबड़ी का शासन 1990 से 2005 तक रहा. ये दोनों इस अवधि में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शासन के शुरुआती सात-आठ साल तक रंजन यादव ही सुपर सीएम की भूमिका में रहे. इस अवधि की महत्वपूर्ण नियुक्तियां इन्हीं की देखरेख में होती थीं.

वे अघोषित रूप से शिक्षा विभाग के सर्वेसर्वा रहे. कुलपतियों की नियुक्तियों के लिए वे अकेले निर्णय लेते थे. 1997 में जनता दल का विभाजन हुआ. राजद बना. लालू प्रसाद अध्यक्ष बने. रंजन यादव कार्यकारी अध्यक्ष बने. राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं. लालू प्रसाद के परिवार के लिए वह संकट का दौर था. पशुपालन घोटाला की सुनवाई हो रही थी. इस मामले में लालू प्रसाद अदालत और जेल की गतिविधियों में उलझे हुए थे.

दोस्ती में कैसे आई दरार- उन्हीं दिनों राजद खेमें में यह चर्चा फैली कि रंजन यादव की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है. संकटग्रस्त लालू परिवार को दरकिनार कर वे स्वयं सीएम बनना चाहते हैं. उन दिनों रंजन यादव के नाला रोड स्थित आवास पर राजद विधायकों का आना-जाना बढ़ गया था. वे अपने घर पर बुद्धिजीवियों की बैठक बुला रहे थे.राज्य सरकार के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे थे. इन गतिविधियों से जुड़ी पुष्ट-अपुष्ट सूचनाएं लालू प्रसाद तक पहुंच रही थी. अविश्वास इस हद तक बढ़ा कि रंजन यादव राजद के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिए गए. लालू और रंजन के बीच मनमुटाव इस स्तर तक पहुंचा कि दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी बन गए. 2009 का वह समय भी आया, जब दोनों पाटलिपुत्र लोकसक्षा क्षेत्र में आमने सामने हुए. परिणाम निकला तो लालू प्रसाद अपने पुराने मित्र के हाथों पराजित हो गए थे. उन्होंने जदयू उम्मीदवार की हैसियत से लालू प्रसाद को पराजित किया.

राजद से साल भर पहले जुड़े

पिछले साल मई में रंजन यादव एकबार फिर राजद से जुड़े. मंगलवार को उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया. हालांकि, वे 80 साल के हैं. इसलिए चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की संभावना नहीं के बराबर है. यह रंजन यादव के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें एक बार फिर पुराने मित्र लालू प्रसाद का सहारा मिला.

मोदी का महाराजा सुहेलदेव वाला दांव

क्या अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर है जवाबी हमला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को साध कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिशें लगातार चल रही हैं. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स को हथियार बनाया.

वे इस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने में कामयाबी हासिल की. वहीं, अब पिछड़ा और दलित समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी है. ऐसे में उन तमाम वर्गों को साधने के लिए लगातार हर स्तर के नेता काम कर रहे हैं. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव में पिछड़ा एवं दलित समुदाय को खासी तरजीह दी. वहीं, अब पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजनीति में अहम माने जाने वाले राजभर समुदाय को साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं. दरअसल, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है.

संसद में चर्चा के क्रम में आया बयान

ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. कांग्रेस उनके निशाने पर रही. उन्होंने कहा कि छोटे राजनीतिक दल और उनके नए नेता कुछ बोलते हैं तो बात समझ में आती है. लेकिन, इतने वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस के नेता भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बयान दे रहे हैं. वह ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

बिहार में विपक्ष की बड़ी तैयारी

पटना. एक तरफ चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और दूसरी ओर बिहार में विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं. चुनाव आयोग मतदाता सूची का मसौदा दस्तावेज जारी करेगा और विपक्ष की तैयारी उसमें कमी खोजने की है. अगर दस्तावेजों की कमी के आधार पर नाम कटते हैं तो विपक्ष सड़क पर उतरेगा.

सिर्फ कानूनी लड़ाई की तैयारी नहीं है, बल्कि सड़क पर बड़े आंदोलन की तैयारी है. विपक्ष के एक बड़े नेता ने पटना में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में अंदाजा जाहिर किया कि एक करोड़ से ज्यादा नाम काटने की तैयारी है. महागठबंधन के एक दूसरे नेता ने, जो पहले एनडीए के साथ रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर एक भी जीवित और मौजूदा मतदाता का नाम कटा तो सरकार देखेगी कि कैसा तांडव होता है.

उनके कहने का मतलब था कि आयोग मृत मतदाताओं के या स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए मतदाताओं के नाम काटता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिहार का मतदाता है, जीवित है और उसका नाम मसौदा सूची में नहीं आता है तो आंदोलन होगा. असल में विपक्षी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि सीमांचल के इलाके में यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट कटेंगे.

इसके अलावा विपक्ष के कोर वोट समीकरण में शामिल जातियों के नाम काटे जा सकते हैं. तभी राजद, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की तीन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को 2024 की मतदाता सूची से लैस करके तैयार रखा है. उनको यह मिलान करना है कि उस सूची में से किसी व्यक्ति का तो नाम दस्तावेज की कमी से तो नहीं कट रहा है. अगर ऐसा होता है तो विपक्ष की पहली कोशिश उसके लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने की है और अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर आंदोलन का रास्ता है.

विशेष | **महाजन जाएंगे संगठन, नार्वेकर बनेंगे मंत्री?**

महायुति से इन विधायकों का पत्ता कट!

मुंबई. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रीमंडल के कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादित बयानों के कारण फंसे मंत्रियों को मुख्यमंत्री बहार करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है.

नई सरकार बनने के बाद छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है, इस दौरान कई मंत्री विवादों में घिरे हैं, जिनमें शिवसेना के नेताओं की संख्या सबसे अधिक है.

विधानसभा के सत्र के दौरान शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की. इसके बाद सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह बेडरूम में सिगरेट पीते दिखे और उनके पास पैसे से भरी एक बैग भी थी. शिरसाट ने खुद बताया कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है. गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का मामला.

चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव- वहीं, ह्रष्टक्के माणिकराव कोकाटे लगातार विवादित बयान देते रहे हैं. विधान परिषद के कामकाज के दौरान उनका रमी खेलते हुए वीडियो भी सामने आया. भाजपा के विधायक गोपीचंद पडलकर ने बिना पास के गंभीर अपराधियों को सीधे विधानसभा में लाया. उन्होंने ह्रष्टक्क के विधायक जितेंद्र आव्हाड के करीबी नितीश देशमुख को भी मारा. इन सभी विवादों के कारण महायुति सरकार की छवि खराब हुई है और स्थानीय निकाय चुनावों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

इन मंत्रियों का पद खतरे में

मुख्यमंत्री फडणवीस कुछ नाकाम और विवादित मंत्रियों को घर का रास्ता दिखा सकते हैं. इसमें शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट, संजय राठोड, भरत गोगावले और योगेश कदम का नाम शामिल हो सकता है. इनके अलावा माणिकराव कोकाटे और नरहरी झिरवल का भी मंत्री पद खतरे में है. खास बात यह है कि भाजपा के संकटमोचक और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी मंत्री गिरीश महाजन को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है. जलसंपदा मंत्री महाजन को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उनके लिए मंत्री पद छोड़ना जरूरी हो सकता है.